भारत की मध्य एशिया तक पहुंच

लेखक- हर्ष वी. पंत और अयाज वानी

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

25 अक्टूबर, 2021

अफ़गानिस्तान की स्थिति ने नई दिल्ली के लिए कई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।

अफगानिस्तान में नाटकीय विकास ने इस क्षेत्र के लिए नई भू-रणनीतिक और भू-आर्थिक चिंताओं को उत्प्रेरित किया है। उभरती हुई स्थिति ने मध्य एशिया और काकेशस के साथ भारत के क्षेत्रीय और द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है, जिससे भारत को इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव के अपने नियमों को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया है।

विदेश मंत्री *एस. जयशंकर* इस महीने की शुरुआत में इस क्षेत्र में थे- चार महीने की अवधि के भीतर उनका तीसरा दौरा था। किर्गिस्तान में, श्री जयशंकर ने विकास परियोजनाओं के समर्थन के लिए $200 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की और उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं (HICDP) पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। उनका अगला पड़ाव था कजाकिस्तान की राजधानी 'नूर सुल्तान'। जहाँ उन्होंने एशिया में बातचीत और विश्वास-निर्माण उपायों (सीआईसीए) पर छठे विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया।

सीआईसीए में, श्री जयशंकर ने चीन के ***बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)*** को निशाना बनाया। बीआरआई को बढ़ावा देने के लिए चीन के तरीकों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक कनेक्टिविटी आवश्यक है, लेकिन इसे संकीर्ण हितों के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने सीमा पार आतं. कवाद के प्रति समर्थन के लिए पाकिस्तान का भी विरोध किया। 13 अक्टूबर को आर्मेनिया पहुँचने से पहले, श्री जयशंकर ने क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए रूस, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के अपने समकक्षों से मुलाकात की।

भारत-आर्मेनिया संबंध

श्री जयशंकर 'आर्मेनिया' की यात्रा करने वाले **पहले भारतीय विदेश मंत्री** बन गए हैं। मंत्री और उनके अर्मेनियाई समकक्ष, अरारत मिर्जोयान, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ाने पर सहमत हुए। यात्रा के दौरान, श्री जयशंकर ने यूरोप के मिन्स्क समूह में सुरक्षा और सहयोग संगठन के तहत अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नागोर्नो-कराबाख संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों का भी समर्थन किया।

अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व फिर से स्थापित करने वाले तालिबान ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) जैसे गठबंधन की कमजोरियों को भी उजागर किया है, जो अफगानिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खतरों के जवाब में बनाया गया था। हालांकि, अधिकांश सदस्य देशों द्वारा एससीओ का उपयोग अपने क्षेत्रीय भू-रणनीतिक और सुरक्षा हितों के लिए किया गया है, जिससे मंच के भीतर *'विश्वास-घाटा और विचलन'* बढ़ रहा है।

जैसा कि एससीओ सामूहिक रूप से अफगान संकट का जवाब देने में विफल रहा, मध्य एशियाई नेताओं ने अगस्त में तुर्कमेनिस्तान में अफगान स्थिति पर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मुलाकात की, और अफगानिस्तान के भीतर और उनकी सीमाओं के साथ मध्य एशियाई आतंकवादी समूहों की उपस्थिति पर भी चर्चा की।

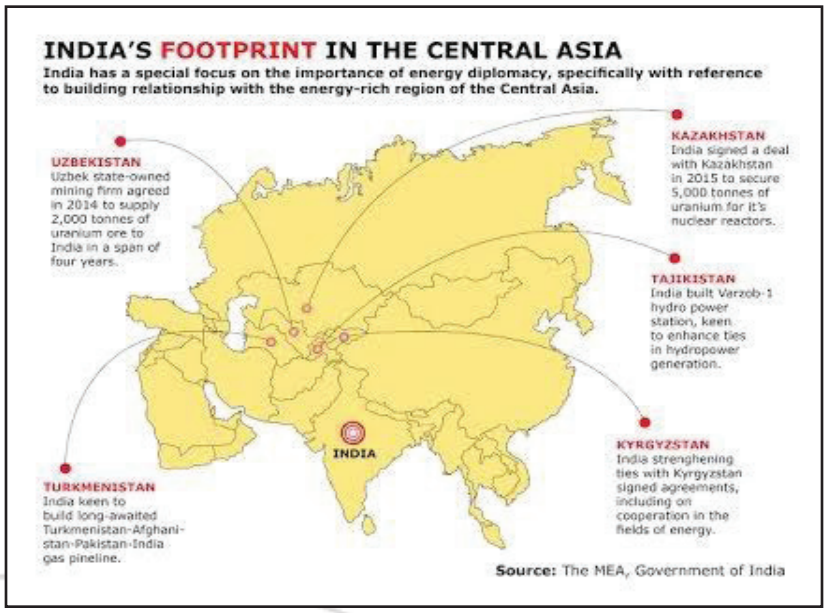

सोवियत संघ के टूटने और मध्य एशिया में स्वतंत्र गणराज्यों के गठन के बाद, भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को फिर से स्थापित किया। भारत ने इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की और राजनयिक संबंध स्थापित किए। नई दिल्ली ने रक्षा सहयोग को प्रोत्साहित करने और व्यापार संबंधों को गहरा करने के लिए कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते (एसपीए) पर हस्ताक्षर किए। 2012 में, नई दिल्ली की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाना था।

हालाँकि, भारत के प्रयासों को पाकिस्तान द्वारा भारत को अपने क्षेत्र से गुजरने की इच्छा की कमी के कारण रोक दिया गया था। चीन ने इस स्थिति का फायदा उठाया और कजाकिस्तान में बहुप्रतीक्षित बीआरआई का अनावरण किया।

बीआरआई के चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के संबंध में बढ़ती भू-रणनीतिक और सुरक्षा चिंताओं और भारत की संप्रभुता के उल्लंघन ने नई दिल्ली को अपनी सुस्त रणनीति को सही करने के लिए मजबूर किया। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों का दौरा किया था। आखिरकार, मध्य एशिया वह कड़ी बन गया जिसने यूरेशिया को नई दिल्ली के हित के क्षेत्र में रखा।

भारत ने सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए 2015 में ईरान के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जो 2003 से उदासीनता में था। अधिकांश मध्य एशियाई नेता भारत के 'चाबहार बंदरगाह' को अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और चीन की महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करने के अवसर के रूप में देखते हैं। चीन के मुखर दृष्टिकोण ने पड़ोसी शिनजियांग में अपने जातीय भाइयों के साथ दुर्व्यवहार पर सामाजिक असंतोष को जन्म दिया।

मध्य एशियाई देश भारत को एक भागीदार के रूप में लेने के इच्छुक हैं क्योंकि उन्होंने अपने रणनीतिक संबंधों में विविधता लाने की मांग की है। उन्होंने नई दिल्ली को अश्गाबात समझौते में शामिल किया है, जिससे भारत को मध्य एशिया और यूरेशिया दोनों के साथ व्यापार और वाणिज्यिक बातचीत की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी नेटवर्क तक पहुंच की अनुमति मिलती है, और इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों तक भी पहुँच मिलती है। क्षेत्र के भीतर चीनी विरोधी भावनाओं में वृद्धि और तालिबान से सुरक्षा खतरों ने नई दिल्ली और मध्य एशिया को अपनी भागीदारी की फिर से कल्पना करने की अनुमति दी है। भारत अपने क्षेत्रीय जुड़ावों को पुनः व्यवस्थित करने में कोई समय गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकता।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में भारत के विदेश मंत्री निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार यात्रा पर गए?

(a) किर्गिस्तान

(b) कजाकिस्तान

(c) अजरबैजान

(d) अर्मेनिया

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Recently to which of the following country did the External Affairs Minister of India visit for the first time?

(a) Kyrgyzstan

(b) Kazakhstan

(c) Azerbaijan

(d) Armenia

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से भारत के लिए अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया की नीति को कार्यान्वित करना व्यवहारिक रूप से कठिन हो गया है।' इस कथन का विश्लेषण करें तथा सेंट्रल एशिया का भारत के लिए महत्व भी स्पष्ट करें। (250 शब्द)

Q. 'After the return of Taliban to power in Afghanistan, it has become practically difficult for India to implement its Connect Central Asia policy.' Analyze this statement and also explain the importance of Central Asia to India. (250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।